भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1049

जिसका उत्तर 05.02.2026 को दिया जाना

डिजिटल राजमार्ग परियोजनाएँ

1049. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र सहित देश भर में कार्यान्वित की जा रही डिजिटल राजमार्ग परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान विशेषकर महाराष्ट्र के संदर्भ में इन परियोजनाओं के लिए अब तक राज्यवार कुल कितनी निधि आवंटित और जारी की गई है;

(ग) इन डिजिटल राजमार्ग परियोजनाओं की वर्तमान भौतिक और वित्तीय प्रगति क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है और इनका समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (घ) सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास एवं अनुरक्षण के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है। एक पायलट पहल के रूप में सरकार द्वारा दो राष्ट्रीय राजमार्गों/राष्ट्रीय एक्सप्रेसवे के निश्चित खंडों के साथ एकीकृत उपयोगिता कॉरिडोर के विकास का कार्य प्रारंभ किया गया है। इस पायलट पहल का उद्देश्य राजमार्ग निर्माण के साथ एकीकृत रूप से ऑप्टिक फाइबर केबल (ओएफसी) अवसंरचना का विकास करना है। सरकार का उद्देश्य इस प्रकार विकसित ओएफसी नेटवर्क को प्रतिस्पर्धी दरों पर आईपी-1 लाइसेंसधारकों को पट्टे पर उपलब्ध कराना है, जिससे दूरसंचार सेवा प्रदाता (टीएसपी), इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी), स्थानीय केबल ऑपरेटर (एलसीओ) आदि इसका उपयोग कर सकें तथा राष्ट्रीय राजमार्गों पर यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ताओं सहित आम जनता को लाभ प्राप्त हो सके। डिजिटल राजमार्ग के विकास हेतु दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे तथा हैदराबाद-

बेंगलुरु कॉरिडोर के कुछ खंडों को पायलट मार्गों के रूप में चिन्हित किया गया है। इन ओएफसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

कॉरिडोर	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र प**	**लंबाई (किमी) / लागत (₹ करोड़)**	**वास्तविक प्रगति**	**वित्तीय प्रगति**	**लक्ष्य पूर्ण करने की तिथि**
दिल्ली - मुंबई एक्सप्रेसवे	दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र	पैकेज-1 (787 किमी / ₹ 108 करोड़)	94%	65%	31.05.2026
		पैकेज-2 (599 किमी / ₹ 88 करोड़)	57%	40%	31.05.2027
हैदराबाद - बेंगलुरु	तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक	पैकेज-3 (500 किमी / ₹ 88 करोड़)	99%	81%	28.02.2026

उपरोक्त पायलट परियोजनाओं के सफल उपयोग पर सरकार द्वारा इस संबंध में किसी भी आगे के विकास पर विचार किया जाएगा।

******